Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide financial assistance for pending irrigation projects in Chatra Parliamentary Constituency, Jharkhand.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा नहीं है। झारखंड के लगभग 76 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं एवं कुल कृषि श्रम शक्ति का 66.85 प्रतिशत कृषि पर आधारित है। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.72 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 29.74 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें से 24.25 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कुल 943.43 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी है, जो कुल कृषि योग्य भूमि का 31.70 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 67 प्रतिशत का है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 13 प्रतिशत ही सुनिश्चित सिंचाई सुविधा के अंतर्गत आता है तथा शेऐा 87 प्रतिशत भाग वर्ष आधारित ही है। कृषि योग्य भूमि को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए राज्य के जल संसाधनों के विकास की बहुत आवश्यकता है। राज्य में कई नदियों का प्रवाह होता है, फिर भी राज्य सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझता है, जिसका मुख्य कारण यहां के जल संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पाना है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान केद्र सरकार एवं झारखंड राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का है। इसके लिए कृषि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था द्वारा सिंचाई में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में पांच सालों (2015-16 से 2019-20) के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

PMKSY में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के अंतर्गत 99 चालू वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में झारखंड की एकमात्र सुवर्ण रेखा बहुद्देशीय योजना शामिल है, जिसके लिए वर्ष 2016-17 में 145.75 करोड़ रुपये दिए गए थे, परंतु वर्ष 2017-18 में कोई राशि नहीं दी गई। इसके अलावा PMKSY के उपघटक कमान क्षेत्र एवं जल प्रबंधन (CAD & WM) के अंतर्गत झारखंड राज्य को क्रमशः वर्ष 2015-16,2016-17, एवं 2017-18 में कोई केद्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई योजनाएं उत्तर कोयल जलाशय, औरंगा जलाशय योजना, अमानत बैराज, गरही, मुहाने एवं मलय आदि परियोजनाएं प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के अलावा गोलाई, दुलकी, अन्जनवा, मलय, चाको, पिरी, सोनरे, रामघाट, नकटीनाला, घाघरी सहित अन्य कई महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं। मैं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से मांग करता हूँ कि वह उपरोक्त वर्णित इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता राशि उपलब्ध करवाने में आवश्यक कार्रवाई करे। साथ ही PMKSY में सुवर्ण रेखा बहुद्देश्यीय योजना तथा उपघटक कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CAD & WM) के अंतर्गत झारखंड राज्य को भी बजट आवंटित किया जाए।